



भरोसे का घोषणा-पत्र

2023-28



भरोसा

बरकरार

फिर से कांग्रेस सरकार





वादा है, फिर निभाएंगे



किसानों का
कर्ज माफ

पहले की तरह इस बार भी होगा किसानों का कर्ज माफ

2018 में कांग्रेस सरकार बनते ही 18.5 लाख किसानों का 9272 करोड़ रुपए कर्जा हमने माफ किया था। इस बार भी कांग्रेस सरकार बनते ही उसी प्रकार कर्जा माफ होगा



अब धान का मिलेगा 3200 रु प्रति क्विंटल

राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को मिलेगी धान की कीमत प्रति क्विंटल 3200 रु



20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी

पहले राज्य सरकार 15 क्विंटल प्रति एकड़ की धान खरीदी करती थी और इस वर्ष से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी शुरू हो गई है



बिजली फ्री 200 यूनिट बिजली फ्री

फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। यानी 200 यूनिट तक की बिजली का बिल नहीं आएगा। 200 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क बिजली मिलेगी।



सभी सरकारी स्कूलों/कॉलेजों में KG से लेकर PG तक शिक्षा मुफ्त

कांग्रेस सरकार बनते ही राज्य के उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर के सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षा एवं प्रवेश शुल्क नहीं देना होगा। स्कूली शिक्षा पूर्ववत् निःशुल्क रहेगी।



गैस सिलेंडर पर 500 रुपए मिलेगी सब्सिडी

फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही सभी आय वर्ग की माताओं एवं बहनों के लिए "महतारी न्याय योजना" लागू कर प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में सरकार द्वारा सीधे जमा की जाएगी।



तेंदूपत्ता बोनस 4000 रु प्रतिवर्ष

राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 4000 रु की जगह अब 6000 रु मिलेंगे और 4000 रु सालाना बोनस अतिरिक्त



17.5 लाख परिवारों को आवास 17.5 लाख गरीब परिवार को हम आवास देंगे

प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र 7.5 लाख परिवारों को केंद्र सरकार ने आवास नहीं दिया है। हम उन सभी 7.5 लाख परिवारों और 10 लाख अन्य जरूरतमंद परिवारों को "मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना" के तहत हम आवास देंगे। इसके लिए हमने आर्थिक सर्वेक्षण करवा लिया है।



10,000 रु
प्रतिवर्ष भूमिहीन मजदूरों को

भूमिहीनों को मिलेंगे 10,000 रु प्रतिवर्ष

राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आने वाले सभी हितग्राहियों को मिलने वाली राशि 7000 रुपए प्रतिवर्ष को बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिवर्ष की जाएगी।



लघु वनोपज
MSP से भी थोड़ा ही अनाज

लघु वनोपजों की MSP पर मिलेंगे अतिरिक्त 10 रु प्रति किलो

हमारी सरकार ने 7 से बढ़ाकर 63 लघु वनोपजों को MSP पर खरीदना शुरू किया है। अब हमारा वादा है कि समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त 10 रुपए प्रति किलो दिए जाएंगे।



अब 10 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त इलाज

डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अब गरीब वर्ग को इलाज के लिए 5 लाख रुपए की बजाय 10 लाख रुपए तक मिलेंगे, साथ ही गरीबी रेखा से ऊपर (APL) को 50 हजार की बजाय अब 5 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकेगी।



अब सभी सरकारी स्कूल बनेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल

राज्य के 6,000 शासकीय हायर सेकेंड्री एवं हाई स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिन्दी मीडियम स्कूलों में क्रमशः अपग्रेड करेंगे।



दुर्घटनाओं का इलाज मुफ्त

छत्तीसगढ़ के निवासियों की सड़क दुर्घटनाओं में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में "मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना" के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएँगे



स्व-सहायता समूह का भी होगा कर्जा माफ

फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही महिला स्व-सहायता समूहों तथा महिलाओं द्वारा सक्षम योजनांतर्गत लिए गए ऋण माफ किए जाएँगे।



तिवरा भी समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी

कांग्रेस की सरकार ने गन्ने से लेकर कोदो, कुटकी व रागी के समर्थन मूल्य घोषित किए थे। इस बार सरकार बनते ही राज्य के किसानों से तिवरा को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा।



जातिगत जनगणना करायी जाएगी

"जिसकी जितनी आबादी, उसका उतना हक" को ध्यान में रखते हुए हम प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाएँगे ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके।



परिवहन व्यावसायियों के होंगे कर व कर्ज माफ

राज्य के परिवहन व्यवसाय से जुड़े 66,000 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक के 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान कर, शासित और ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी



युवाओं को उद्योग व्यवसाय ऋण में 50% सब्सिडी

युवाओं को उद्योग व्यवसाय के लिए ऋण पर अब तक 40% सब्सिडी दी जाती थी। अब इसे बढ़ाकर 50% सब्सिडी के साथ ऋण की सुविधा मिलेगी



700 नए RIPA का होगा निर्माण

फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही आगामी वर्षों में 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों (रीपा) की स्थापना करेंगे। इससे ग्रामीण औद्योगिक केंद्र की संख्या 300 से बढ़ाकर 1000 हो जाएगी।



अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनते ही शहरी निकाय क्षेत्रों में अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध सरकार की ओर से किया जाएगा



भरोसा

बरकरार

फिर से कांग्रेस सरकार

पंजा का बटन दबाएंगे
कांग्रेस को जिताएंगे



छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी